साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 18-24 जुलाई 2022, वर्ष-8, अंक-15

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले: पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली सफलता पर आभार भी व्यक्त किया

मुरैना में स्थापित होगा केंद्रीय बीज फार्म सरकार देगी 885.344 हेक्टेयर भूमि

-कृषि उपज मंडी नियम 2009 में भी प्रस्तावित संशोधन किया

-तालाब से निकलने वाली मिट्टी पर भी नहीं लगेगी रायल्टी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की। जिसमें सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली सफलता पर आभार भी व्यक्त किया और पूरी कैबिनेट टीम को बधाई दी। इसके अलावा सीएम ने प्रदेश में लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्रि-परिषद ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्रालय को बीज फार्म स्थापित करने के लिए जिला मुरैना में 4 ग्रामों में स्थित क्रमशः ग्राम मौजा जाखौना कुल किता 50 रकबा 339.104 हेक्टेयर, ग्राम रिठौराखुर्द कुल किता 59 रकबा 201.247 हेक्टेयर, ग्राम गडौरा कुल किता 27 रकबा 134.91 हेक्टेयर में से 111.31 हेक्टेयर एवं ग्राम गोरखा कुल किता 37 रकबा 233.683 हेक्टेयर कुल रकबा 885.344 हेक्टेयर शासकीय भूमि निःशुल्क प्रीमियम तथा एक रुपए वार्षिक भू-भाटक लेकर आवंटित करने का निर्णय लिया। कुल मिलाकर मुरैना में बीज फार्म स्थापना के लिए 885.344 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मंडी फीस की प्रतिपूर्ति

प्रदेश के निर्यात को प्रोत्साहन देने और किसानों को उनकी उपज गेहूं के बेहतर मूल्य दिलाने एवं राष्ट्रीय निर्यातकों/कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पात्र निर्यातकों को मंडी फीस की प्रतिपूर्ति की जाना है। गेहूं के निर्यातकों को गेहूं क्रय में भुगतान की गई मंडी फीस की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रस्तावित योजना एवं परिप्रेक्ष्य में निर्यातकों के लिए स्पष्ट प्रावधान करने के लिये कृषि उपज मंडी अधिनियम के अधीन राज्य शासन द्वारा निर्मित नियम मप्र कृषि उपज मंडी नियम में संशोधन की कार्रवाई के लिए निर्णय लिया गया। तदनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

मध्यम सिंचाई परियोजना

सतना जिले की दौरीसागर मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 227 करोड़ 56 लाख रुपए सैच्य क्षेत्र 7,200 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सतना जिले की मझगवां तहसील के 15 ग्रामों के 7200 हेक्टेयर रकबे में भूमिगत पाइप लाइन द्वारा प्रेशराइज्ड पद्धति से रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी एवं मंदाकिनी नदी के सतत प्रवाह के लिए आवश्यक जल उपलब्ध होगा।

'जागत गांव हमार' की साइड स्टोरी

तिलहन फसलों के उगाए जाएंगे बीज

जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। भारतीय बीज निगम लिमिटेड फार्म हाउस बनाने जा रहा है। 7 हजार हेक्टेयर के इस फार्म में तिलहन फसलों के बीजों को उगाया जाएगा। साथ ही, तेल निकालने की फैक्टरी लगाई जाएगी। इसमें हजारों किसानों, ठेकेदारों और स्थानीय स्तर के श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। कैबिनेट की बैठक से पहले भारतीय बीज निगम लिमिटेड की टीम जिले के अपर कलेक्टर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मिली। इसके बाद टीम ने सबलगढ़ के तीन गांवों में जमीन देखी। जिले में लंबे समय से बड़े शासकीय औद्योगिक उपक्रम की कमी थी, जिससे स्थानीय स्तर के लोगों को रोजगार मिल सके। इस कमी को जल्द ही पूरा होने की संभावना है। राष्ट्रीय बीज निगम जिले में बड़ा फार्म हाउस बनाने जा रहा है। अधिकारियों का दल क्षेत्रीय प्रबंधक गुलबीर पवार के नेतृत्व में आया। दल के सदस्य अपर कलेक्टर नरोतम भार्गव से मिले। दल के सदस्य सबलगढ़ पहुंचे। यहां वहां के तीन गांव धौंसा, सेमई और बरखापुर गांव में जमीन देखी।

इन बीजों की करेंगे पैदावार

आज भी भारत के पास अच्छी किस्म के तिलहन के बीज नहीं हैं। सरकार को हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर विदेशों से तिलहनी बीज को आयात करना पड़ता है। फार्म में तिलहन बीजों के फाउंडेशन, ब्रीडर व प्रमाणित बीजों का उत्पादन होगा। बीजों की किस्मों को कृषि विवि, कृषि विज्ञान केंद्रों में तैयार किया जाता है। बाद में बीज निगम उन बीजों की पैदावार करता है। बीज निगम के अभी तक 23 हजार हेक्टेयर जमीन तक के फार्म बने हैं। राजस्थान में 6 हजार हेक्टेयर जमीन के फार्म हैं। हिसार व कर्नाटक में 25-25 हजार हेक्टेयर के फार्म हैं।

दूसरे राज्यों में भी जाएगा चंबल का तैयार बीज

टीम के सदस्यों ने चंबल क्षेत्र का भी मुआयना किया। टीम के सदस्यों का मानना है, अगर चंबल का रिवाइन एरिया, तिलहनी फसलों के बीजों की पैदावार के लिए उपयुक्त होता है, तो वह वहां भी फार्म बनाएंगे। बीज निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, गुलबीर सिंह पवार ने बताया कि वह सर्वे रिपोर्ट दिल्ली में अधिकारियों को सौपेंगे। उसके बाद जमीन मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा। यहां ब्रीडर व सर्टिफाइल सीड तैयार करेंगे। चंबल क्षेत्र के 10 जिले लगते हैं। अन्य राज्यों को भी बीज मिल सकेगा।

सरकार किसानों से 7,275 रुपए प्रति क्विं. खरीदेगी मूंग

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार मूंग खरीद के पंजीयन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी करने जा रही है। व्यापरियों ने मंडियों में 4200 से 5800 रुपए प्रति क्विंटल किसानों की मूंग खरीदी है। ज्यादातर किसानों का कहना है की व्यापारियों ने अच्छी मूंग भी कम दामों में खरीदी है, सरकार का यह फैसला बहुत देर से आया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने मप्र में मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का ऐलान करते हुए बताया कि इस साल किसानों की मूंग की फसल का समर्थन मूल्य 7275 रुपए क्विंटल तय किया गया है। मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सीएम ने कहा कि मप्र में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में बहुत कम हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि मूंग को समर्थन मूल्य 7,275 रुपए क्विंटल खरीदेंगे।

2.25 लाख टन खरीदी का लक्ष्य

मध्य प्रदेश में इस वर्ष केंद्र सरकार ने केवल 2 लाख 25 हजार टन मूंग खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि मूंग का उत्पादन 15 लाख टन से अधिक हुआ है। इसे देखते हुए सरकार ने पूरी मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदने की केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। यह अनुमति मिल जाने पर राज्य सरकार पर वित्तीय भार नहीं आएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने कोटा से ज्यादा खरीदने से मना कर दिया है।

सोमवार से ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। किसानों के पंजीयन के लिए राज्य सूचना केन्द्र को सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीयन कार्य 28 जुलाई तक किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 30 जिलों में होगी। उड़द की खरीदी 9 जिलों में की जाएगी।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

राज्य उपभोक्ता आयोग का आठ साल बाद आया फैसला-कहा-कम समय के लिए किसान घर में ही नहीं रख लेता

शीतगृह में रखा 181 बोरी आलू सड़ा, किसान को मिलेगा सवा लाख हर्जाना

भोपाल। शीतगृह में रखे उत्पाद का मूल्य कम होने या बढ़ने का बहाना बनाकर शीतगृह संचालक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उसे उत्पाद की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह निर्णय राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक किसान के प्रकरण में सुनवाई करते हुए सुनाया है। आठ साल पुराने प्रकरण में हुए निर्णय के अनुसार 181 बोरी आलू खराब होने के मामले में शीतगृह संचालक को अब सवा लाख रुपए हर्जाना चुकाना होगा। शाजापुर के किसान हरीश कुमार ने भागीरथ कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) प्रायवेट लि. के संचालक रामेश्वर सिंह के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में 2012 में याचिका लगाई थी। किसान ने शिकायत की थी कि उसने अक्टूबर 2011 में शीतगृह में 181 बोरी आलू रखा था, लेकिन शीतगृह वातानुकूलित नहीं होने के कारण आलू सड़ गया। इससे करीब साढ़े तीन लाख का नुकसान हुआ।

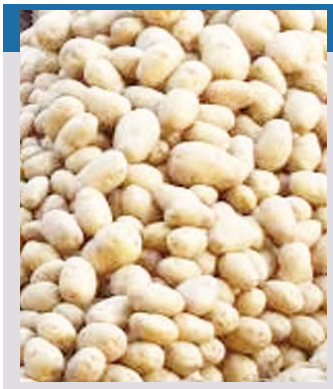

शीतगृह संचालक बोला-आलू का भाव कम था

शीतगृह संचालक ने तर्क रखा था कि अक्टूबर 2011 में आलू का भाव बहुत कम था, बल्कि शीतगृह का किराया अधिक था। इसलिए किसान ने आलू नहीं उठाया। आलू निश्चित समयावधि में नहीं निकालने पर सड़ जाते हैं, जबकि उसने किसान को आलू ले जाने के लिए सूचना दी थी। वहीं किसान का कहना था कि आलू के भाव कम-ज्यादा होता रहता है। राज्य आयोग ने शीतगृह संचालक के तर्क को खारिज कर दिया और संचालक को फटकार लगाते हुए कहा कि आलू शीतगृह में रखा था कि किसान उसे कभी भी ले जा सकता है। अगर कुछ दिनों के लिए आलू रखना था तो वह घर में ही रख लेता।

11 साल बाद मिला न्याय

जिला उपभोक्ता आयोग ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शीतगृह संचालक पर करीब डेढ़ लाख रुपए का हर्जाना देने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर शीतगृह संचालक ने राज्य उपभोक्ता आयोग में 2014 में अपील लगा दी। राज्य आयोग ने 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू की कीमत एक लाख आठ हजार 600 रुपए तय की। साथ ही पांच हजार मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपए वाद व्यय लौटाने का आदेश दिया। किसान को 11 साल बाद न्याय मिला।

मामले में जिला आयोग ने शीतगृह संचालक के खिलाफ निर्णय सुना दिया था। इसके बाद शीतगृह संचालक ने राज्य आयोग में अपील लगाई थी। यहां भी किसान के पक्ष में निर्णय हुआ है।

- संभावना राजपूत, किसान की वकील

धार के किसान सालाना कर रहे लाखों की कमाई

मप्र की ककड़ी देश-विदेश में हो रही सप्लाई

धार। जागत गांव हमार

जिले के मनावर विकासखंड में किसान इंटर क्रॉपिंग टेक्निक से खेती कर रहे हैं। किसानों ने कपास के साथ ककड़ी की फसल लगाई है। एक बार कपास और ककड़ी की फसल लगाने के बाद सालभर में तीन बार उपज मिल जाती है। इससे कम लागत पर ज्यादा मुनाफा हो रहा है। यहां की ककड़ी देश के बड़े शहरों के साथ विदेशों में सप्लाई की जा रही है। व्यापारी सीधे खेतों से खरीदी कर इसे देश-विदेश में भेज रहे हैं। एक बीघा में ककड़ी की फसल लगाने की लागत 5 हजार आती है। इससे सालाना एक लाख से ज्यादा की कमाई हो जाती है। खेती किसानी सीरीज में **'जागत गांव हमार'** किसानों को बताने जा रहा है कि कपास के साथ ककड़ी की फसल लगाकर कैसे कमाई की राह बनाई जा सकती है।

किसान हरिशंकर सोलंकी, माधव पाटीदार, हरिओम पाटीदार ने बताया कि खीरा ककड़ी से हमें जीवन में पहली बार किसी सब्जी में इतने पैसे की बचत हुई है। ककड़ी की फसल के लिए प्रति बीघा 5 हजार का खर्च आता है। इससे 35 हजार रुपए की उपज एक बार में होती है।

एक फसल से तीन बार उत्पादन लेते हैं। वहीं, कपास की प्रति बीघा की फसल में 16 हजार की लागत आती है। एक बार में 7 क्विंटल उत्पादन होता है। 8000 रुपए के भाव से एक बार में 56 हजार की कमाई होती है। सालाना 1 लाख 68 हजार तक कमाई हो जाती है।

15 रुपए किलो ले रहे व्यापारी

क्षेत्र की खीरा ककड़ी की बड़ी डिमांड बनी हुई है। 650 किमी दूर मनावर आकर जयपुर के व्यापारी किसानों के खेत से ही खरीदी कर लेते हैं। ये किसानों को 15 रुपए किलो के हिसाब से भुगतान करते हैं। इसके बाद वे जयपुर और गुड़गांव के प्लांट में ले जाकर वैक्यूम पैक कराते हैं। यहीं से ताजी ककड़ी भारत के बाहर अरब देशों में

इंटरक्रॉपिंग का फायदा

इंटरक्रॉपिंग का अर्थ खेत के बीच-बीच में या खाली जगह में कोई दूसरी फसल लेना है। उदाहरण के लिए गन्ने का अंकुरण और वृद्धि मंद होती है। बीच में फसल ली जा सकती है, क्योंकि इस फसल की रोपाई खाली स्थान छोड़कर की जाती है।

गर्मियों में काफी डिमांड

कद्दूवर्गीय फसलों में खीरा का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। गर्मियों में खीरे की बाजार में काफी मांग रहती है। यह गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफी फायदेमंद बताया गया है। खीरे की गर्मियों में बाजार मांग को देखते हुए जायद सीजन में इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है।

रेतीली जमीन पर उत्पादन

खीरे का उपयोग वजन को कम करने और सलाद के रूप में किया जाता है। बाजार में इसकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। खीरे की खेती रेतीली भूमि में अच्छी होती ऐसे में किसान के पास जो ऐसी भूमि है, जिसमें दूसरी फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होता है उसी भूमि में खीरे की खेती से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है।

जैविक खाद के साथ करें तैयारी

खेती की तैयारी के 15-20 दिन पहले 20-25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद मिला देते हैं। खेती की अंतिम जुताई के समय 20 किग्रा नाइट्रोजन, 50 किग्रा फास्फोरस व 50 किग्रा पोटाशयुक्त उर्वरक मिला देते हैं। फिर बोवनी के 40-45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग से 30 किग्रा नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में प्रयोग की जाती है। जायद में उच्च तापमान के कारण अपेक्षाकृत अधिक नमी की जरूरत होती है। अत: गर्मी के दिनों में हर सप्ताह हल्की सिंचाई करना चाहिए। बारिश के मौसम में सिंचाई बरसात पर निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन फसल में 4-5 दिनों के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षाकालीन फसल में अगर बारिश न हो, तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।

बोवनी के दो माह बाद ही फल

किसानों को खीरे की बुवाई करने से पहले उन्हें रोगों से बचाने के लिए उपचारित करना चाहिए। अच्छा उत्पादन लेने के लिए 20-25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी चाहिए। खीरा बहुत जल्दी तैयार होने वाली फसल है। इसकी बोवनी के दो महीने बाद ही इसमें फल लगना चालू हो जाते हैं।

खीरे की उन्नत किस्में

भारतीय किस्में: स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूना खीरा, पंजाब सलेक्शन, पूसा संयोग, पूसा बरखा, खीरा 90, कल्यानपुर हरा खीरा, कल्यानपुर मध्यम और खीरा 75 आदि प्रमुख है।

नई किस्में: पीसीयूएच- 1, पूसा उदय, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण शीतल आदि प्रमुख हैं।

संकर किस्में: पंत संकर खीरा- 1, प्रिया, हाइब्रिड- 1 और हाइब्रिड- 2 आदि प्रमुख हैं।

विदेशी किस्में: जापानी लौंग ग्रीन, चयन, स्ट्रेट- 8 और पोइनसेट आदि प्रमुख हैं।

खीरे की खेती के लिए नवंबर के महीने में प्लास्टिक के गिलास में मिट्टी भरकर बीज अंकुरित करने के लिए डालते हैं। दो माह बाद खेतों में रोपाई की जाती है। बीज तैयार करने का यह वैज्ञानिक तरीका भरपूर उत्पादन देता है। खीरे की खेती से अच्छी आमदनी के लिए किसान हाइब्रिड प्रजाति को प्रमुखता देते हैं।

महेश बर्मन, वरिष्ठ एसडीओ, कृषि विभाग, धार

छतरपुर में बारिश के बाद शुरू हुई खेती, उपसंचालक ने फसलों का निरीक्षण किया

छतरपुर। उप संचालक कृषि मनोज कश्यप द्वारा जारी खरीफ सीजन में किसानों द्वारा ग्राम मातगुवां, चौका एवं खैंरो में की बुवाई गई मूंगफली उड़द एवं तिल फसलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि बोवनी की गई फसलों में अभी अंकुरण एवं सामान्य अवस्था में है। किसानों को फसलों से नीदा खरपतवार निकालने की सलाह दी गई। खरपतवार निकालने के लिए खेतों की डोरा कुल्फा यंत्र चलाकर फसले की गुड़ाई करें तथा खरपतवार को भी नष्ट कर सकते है।

आवश्यकतानुसार नीदानाशक दवाओं का भी उपयोग करें जिसमे शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों प्रति हेक्टर 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रुपए अनुदान प्रावधान है। जिसमे कीटनाश्क नीदानाश कलायशेन्स धारी दुकान से क्रय कर रसीद अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी के माध्यम से आवेदन भेजे। अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में डाल दी जाएगी। जिन किसानों ने बोवनी नहीं की है ऐसे किसान अभी 30 जुलाई तक तिल, उड़द व मूंग फसल एवं अन्य फसलों की बोवनी कर सकते है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र मे बीते कई वर्षों से विलम्ब से बर्षा होने के कारण इस क्षेत्र का क्रापिंग पैटर्न भी इसी मौसम के अनुकूल कम दिनों की किस्मों को प्राथमिकता से बोवनी कर समान्य उत्पादन लें सकते हैं। किसानों को बर्षा को ध्यान मे रखते हुए किसान के पास थोड़ा सा भी पानी है तो स्पिंकलर से सिंचाई कर फसलों अधिक उत्पादन इस क्षेत्र मे भी लिया जा सकता है।

बीमा राशि का देना होगा दो प्रतिशत प्रति हेक्टेयर

किसान खरीफ की फसलों का कराएं बीमा पीएम फसल बीमा योजना का मिलेगा लाभ

भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ की फसलों का समय पर बीमा कराकर किसान बरसात में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को फसल के हिसाब से दो या पांच प्रतिशत राशि के चुकानी पड़ती है। बरसात के मौसम में अधिसूचित फसलों का बीमा ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 जुलाई तक करवा सकते है। अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र या फसल बीमा पोर्टल पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को बीमा के लिए योजना को ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से दो दिवस पूर्व यानि 29 जुलाई तक सबंधित बैंक को निर्धारित प्रपत्र में लिखित में आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते है।

देना होगा दो प्रतिशत

उप संचालक कृषि ने बताया कि किसान द्वारा देय प्रीमियम-खरीफ मौसम में अधिसूचित फसले सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल की बीमित राशि का अधिकतम दो प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम किसानों द्वारा देय करना होगी। कपास फसल के लिए बीमित राशि का अधिकतम पांच प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम किसानों द्वारा देय होगी।

यह लगेंगे दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र-शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, खसरा, खतौनी, बुवाई प्रमाण पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी, दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

जैविक खेती का अलख जगाने हरियाणा से चला युवक नेपानगर पहुंचा

» एक लाख किमी से ज्यादा के भ्रमण का लक्ष्य

» अब तक 44 हजार किलोमीटर का सफर किया

नेपानगर। रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर जैविक खेती अपनाने के लिए किसानों को जागरूक करने एक युवक हरियाणा से साइकिल यात्रा पर निकला है। 26 साल के नीरज प्रजापति ने एक लाख 11,111 किमी की साइकिल यात्रा का लक्ष्य तय है। नीरज को द मैन ऑफ बाइसिकल एग्रीकल्चर इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग कम कर जैविक खेती को बढ़ाना है। हाल ही में साइकिल से नेपानगर पहुंचे नीरज ने बताया कि वर्तमान में किसान खेतों में रासायनिक खाद का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। जिसका विपरीत असर मनुष्य की सेहत पर पड़ रहा है। इसकी रोकथाम और जैविक पद्धति को अपनाते हुए फसल की सुरक्षा को लेकर किसानों को जानकारी उपलब्ध करावा रहे हैं। उसने बताया कि गत नौ अप्रैल 2019 से यात्रा शुरू की थी। अब तक 44,660 किमी की यात्रा कर चुका है। हरियाणा से यात्रा शुरू करने के बाद राजस्थान, उत्तरप्रदेश में किसानों को जागरूक कर चुके हैं। अब मध्यप्रदेश में हैं और आगे महाराष्ट्र जाएंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले-किसानों के हित में केंद्र-राज्य सरकारें मिलकर कर रहीं काम

गांवों में बैठे छोटे किसानों के जीवन में तब्दीली लाने के लिए सबको मिलकर करना होगा काम

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर कृषि के क्षेत्र में हर संभव कार्य कर रही है, फिर भी कृषि के समक्ष चुनौतियों के मद्देनजर इनका समाधान करना, इनके लिए पालिसी बनाना तथा इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन करना हम सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां वैचारिक, भाषाई, भौगोलिक व जलवायु की विविधता है, लेकिन यहीं भारत की ताकत है। इसका कृषि के संदर्भ में भी राज्यों व देश के हित में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। कृषि बहुत संवेदनशील क्षेत्र है जो करोड़ों किसानों से जुड़ा है। गांवों में बैठे छोटे किसानों के जीवन में केंद्र-राज्य मिलकर कैसे तब्दीली ला सकते हैं, इसके लिए लोभ संवरण करे बिना काम करना चाहिए। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरू में आयोजित राज्यों के कृषि व बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कही। इस अवसर पर केंद्रीय रसायन व उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद थे। तोमर ने कहा कि देश में खाद के आयात पर हमारी निर्भरता है और केंद्र सरकार द्वारा सालाना लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी इसमें किसान हित में दी जा रही है, ताकि विदेशों में बढ़ती कीमतों का भार हमारे किसानों पर नहीं पड़े लेकिन इस स्थिति का कहीं तो अंत होना चाहिए। इसलिए अब फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर होने, मेक इन इंडिया की आवश्यकता है। तोमर ने नैनो फर्टिलाइजर का महत्व बताते हुए कहा कि इसे बढ़ावा देने में राज्यों की भूमिका अहम है। किसानों की मेहनत,वैज्ञानिकों की कुशलता व केंद्र-राज्यों की नीतियों के कारण देश में कृषि का बेहतर विकास हुआ और सतत हो रहा है। उन्होंने राज्यों के मंत्रियों से कहा कि कृषि की और तेजी से प्रगति के लिए अपने कार्यकाल में श्रेष्ठ कार्य कर गुजरें।

भारत में डीएपी के दाम सबसे कमः मांडविया

सम्मेलन में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मांडविया ने खाद की वैश्विक स्थिति बताते हुए कहा कि भारत को इसे काफी मात्रा में आयात करना पड़ता है, रा-मटेरियल भी बहुत महंगा है, इसके बावजूद केंद्र सरकार अत्यधिक सब्सिडी दे रही है। डीएपी पर सब्सिडी को 2020-21 में 512 रुपए से बढ़ाकर 2022-23 खरीफ सीजन के लिए 2501 रुपए कर दिया गया है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में डीएपी के दाम सबसे कम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, किसानों पर बढ़ी लागत का बोझ नहीं डाला जा रहा है। इसके सुगम वितरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन अब देश में अभियान के रूप में नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने राज्यों से इस संबंध में सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि फर्टिलाइजर की उपलब्धता का जिलेवार हिसाब-किताब रखा जाए ताकि उसका समुचित प्रबंधन एवं वितरण हो सके। किसानों का फर्टिलाइजर कहीं उद्योगों को नहीं चला जाए, इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि देशभर में माडल आउटलेट्स की शीघ्र ही लांचिग होगी।

खाद्यान्न उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भरः बोम्मई

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि कृषि हमारी संस्कृति है,कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और भारतीय कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 8 साल में कृषि क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई और ठोस कार्य हुए हैं। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी होने के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन में हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ है। बोम्मई ने कहा कि जो देश खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी होता है, वह स्वाभिमानी राष्ट्र बनता है। अगर किसान जमीन से अलग हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए किसानों को जमीन से जोड़े रखना एवं उन्हें और भी मजबूत करना है। किसानों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सब तरफ से मजबूत करना होगा।

कृषि और किसान केंद्रित केंद्र की नीतियां: पटेल

बेंगलुरु में कृषि मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मप्र के किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि देश में पहली बार कृषि और किसान केन्द्रित नीतियां मोदी सरकार के नेतृत्व में बनाई और क्रियान्वित की जा रही है। केंद्र सरकार नीतिगत फैसले लेकर किसानों और देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिए न केवल बेहतर नीतियां बनाई गई बल्कि उन्हें क्रियान्वित भी किया गया है। इसी का परिणाम है अब धीरे-धीरे खेती लाभ का धंधा बनने लगी है। कृषि और किसान को समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस काम की शुरुआत तब हुई जब अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र पर फोकस किया और कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में काम किए हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उन्होंने अभिनव प्रयोग शुरू किए जो सफल भी रहे हैं। आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से अब कृषि लाभ का धंधा बन रहा है और देश का किसान आत्मनिर्भर हो रहा है।

खेत में बिछी केला फसल देखकर बेहोश हुआ किसान

बुरहानपुर के दो दर्जन गांवों में केला की फसल बर्बाद

-किसानों की मांग-फसल बीमा जल्द किया जाना चाहिए

बुरहानपुर। जागत गांव हमार

जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। अभी हाल ही में तेज हवाओं के साथ करीब डेढ़ घंटे झमाझम बारिश हुई। जिससे लोगों को उमस और गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन किसानों को आंधी से लाखों का नुकसान हुआ है। जिले के दो दर्जन गांवों में तैयार केला फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। नेपानगर क्षेत्र के दस से अधिक गांवों में केला फसल चौपट हो गई।

रतागढ़ गांव के 60 वर्षीय किसान हरि सावले भी केला फसल का हाल जानने खेत पहुंचे थे। सत्तर प्रतिशत तक केले के पौधे खेत में बिछे देखकर वे बेहोश हो गए। किसान का कहना था कि कुछ दिन पहले भी आंधी से फसल को नुकसान पहुंचा था। सरकार की ओर से पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। रतागढ़ के अलावा क्षेत्र के सारोला, अंबाड़ा, देवरी, नेवरी, डवाली खुर्द, शंकरपुरा, मानमोढ़िया, नावथा, सोनूद में भी केला फसल को भारी नुकसान हुआ है।

जैनाबाद क्षेत्र में भी नुकसान

नेपानगर के साथ ही जैनाबाद क्षेत्र और शाहपुर में भी केला फसल को नुकसान हुआ है। कुछ किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उमर्दा के किसान गोपाल पाटिल के दो हजार पौधे, गोटिया पटेल के चार हजार, दिगंबर पटेल के दो हजार, योगेश चौधरी के दो हजार, यशवंत पटेल के दो हजार, ईश्वर पटेल के दो हजार केले के पौधे गिर गए हैं। इसी तरह अंबाड़ा गांव के आधा दर्जन से ज्यादा किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है।

तहसीलदार-पटवारी ने किया निरीक्षण

आंधी से केला फसल बर्बाद होने की सूचना मिलने के बाद राजस्व अमला सर्वे के लिए मैदान में उतर गया है। रतागढ़ के किसान बद्रीनाथ सपकाले ने बताया कि साढ़े चार एकड़ में लगी केली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तहसील में सूचना देने के बाद तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने पटवारियों का दल गठित कर सर्वे के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद शासन के नियमानुसार किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने से आक्रोश

बार-बार प्राकृतिक आपदा से केला फसल खराब होती है, लेकिन इसे अब तक फसल बीमा के दायरे में नहीं लाया गया है। जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। किसान बीते तीन साल से फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग कर रहे हैं। अंबाड़ा के किसान प्रताप राजाराम पाटिल ने बताया 2018 में किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला था। पिछले तीन साल से इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि महाराष्ट्र में केला उत्पादक किसानों को यह लाभ मिल रहा है। बुरहानपुर जिले में 60 हजार एकड़ में केला की फसल होती है। इसकी खेती से तीस हजार से अधिक किसान जुड़े हैं। आंधी व वर्षा से केला फसल खराब होने पर उसे उखाड़कर फेंकना पड़ता है। पिछले साल सीएमवी वायरस के कारण केले के पौधे उखाड़कर फेंकने पड़े थे। किसानों की मांग है कि फसल बीमा जल्द किया जाना चाहिए।

- आंधी से केला उत्पादक किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मैंने भी कुछ गांवों का भ्रमण कर स्थिति देखी है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद वास्तविक नुकसानी का पता चलेगा। किसानों को फिलहाल फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

- आरएनएस तोमर, उपसंचालक उद्यानिकी, बुरहानपुर

हरियाली पर्व पर विशेष

वृक्ष नहीं तो धरती पर जीवन भी नहीं

बरसात का मौसम शुरू होते ही देशभर में वन महोत्सव, हरियाली और हरेला नाम से क्षेत्र विशेष की भाषा और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वृक्षारोपण पर्व मनाए जा रहे हैं। बरसात का यही सीजन है जिसमें पौधों को अपने बाल्यकाल में पर्याप्त जल के साथ ही वातावरण में नमी और तापमान मिल जाता है। बरसात का मौसम शुरू होते ही देशभर में वन महोत्सव, हरियाली और हरेला नाम से क्षेत्र विशेष की भाषा और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वृक्षारोपण पर्व मनाए जा रहे हैं। बरसात का यही सीजन है जिसमें पौधों को अपने बाल्यकाल में पर्याप्त जल के साथ ही वातावरण में नमी और तापमान मिल जाता है।

हमारे देश में वृक्षों के प्रति पहली बार चेतना जागृत नहीं हो रही है। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा मानव जीवन के लिए वनों और पर्यावरण चेतना को लेकर भारत को विश्वगुरू के रूप में स्थापित कर चुके हैं। उनसे भी पहले भारत के पहले केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री केएम मुंशी सन 1950 में वन संरक्षण और पेड़ लगाने के लिए लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत कर चुके थे। यह त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग दिनों में मनाया जाता है। केएम मुंशी से भी पहले सन 1730 में अमृता देवी विश्नाई वृक्षों की रक्षा के लिए सेकड़ों लोगों के साथ बलिदान देकर दुनिया में ऐसी मिसाल पेश कर चुकी हैं, जो न भूतो और न भविष्यति है। वास्तव में 1730 में राजस्थान के मारवाड़ में खेजडली में जोधपुर के महाराजा द्वारा हरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, अमृता देवी विश्नाई ने अपनी तीन बेटियों आसू, रत्नी और भागू के साथ अपने प्राण त्याग दिए। उनके साथ 363 से अधिक अन्य बिश्नोई, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए मर गए। विश्नोई समाज आज भी वृक्षों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए विश्व के लिए एक उदाहरण है। वृक्षों के लिए सपरिवार अपने प्राण गंवाने वाली अमृता देवी का कहना था कि अगर किसी के सिर की कीमत पर भी एक पेड़ बचाया जाता है, तो यह इसके लायक है। यही कारण है कि भारत में पेड़ों से जुड़े इतने सारे त्योहार हैं। उनमें से एक वन महोत्सव दिवस या वन दिवस है। इसे धरती मां को बचाने के ऊंचे उद्देश्य से धर्मयुद्ध के रूप में आजादी के तत्काल बाद केएम मंशी ने शुरू किया था। लेकिन समाज में ऐसे भी तत्व हैं जिनको समाज या मानवता से नहीं, बल्कि केवल अपने निजी हितों से मतलब है या जिनकी नजर में प्रकृति गौण और विकास की चकाचौंध अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जब अपनी आजीविका के लिए दूसरों की हत्या का पेशा अपना सकते हैं तो वन तस्करों के लिए पेड़ों की हत्या गाजर मूली काटने के समान ही है। झूम

खेती करने वालों की तरह कुछ के लिए पेड़ काटना आजीविका के लिए जरूरी है तो कुछ अज्ञानतावश पेड़ काट कर खेती करते हैं। वास्तव में हम एक वृक्ष का मूल्य केवल उसकी लकड़ी या ज्यादा से ज्यादा उसके फल और घास से आंकते हैं। जबकि उसका इससे भी कहीं अधिक परोक्ष महत्व है जो दिखाई नहीं देता है। वृक्ष वातावरण से कार्बनडाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो जीवन संभव नहीं है। बिना ऑक्सीजन के आदमी कुछ ही मिनटों में प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार वृक्ष को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ऑक्सीजन देने के अलावा, पेड़ पर्यावरण से विभिन्न हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होता है। इसे कार्बनस्टॉक के रूप में आंका जाता है। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि मानी गयी है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन बताया गया है। प्रकृति ने वनस्पति और जीवधारियों के लिए ये ऐसा रिश्ता तय किया है जो कि अटूट है और अगर इसे तोड़ा गया तो दोनों का ही अस्तित्व नहीं है। आज हम भोजन के रूप गेहूं की रोटी या चावल खाते हैं तो गेहूं और धान कभी जंगल की उपज ही रही होगी। इसी तरह रोटी और भात के साथ सब्जियों और दालों का मूल श्रोत भी जंगल ही है। जनजातियां तो आज भी भोजन के लिए वनोपज पर निर्भर हैं। हमारे दैनिक जीवन के उपयोगी पशु जैसे भैस, गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि इन सभी का मूल भी तो वन ही हैं। हमने तो हाथी को भी अपने मतलब के लिए पालतू बना दिया। पैसे कमाने के लिए शेर और बाघ को भी पिंजरे में बंद कर दिया था जिसे अब जाकर अदालत ने सर्कसों के पिंजरों से उन्हें आजाद किया। लेकिन वन्य जीवों और उनके अंगों की तस्करी अब भी चल रही है। पेड़ हमें भोजन और आश्रय भी प्रदान करते हैं। कई पेड़ों के फल पक्षियों और जानवरों के भोजन के काम आते हैं और जीव उनके बीज फैला कर वृक्ष के पुनर्जीवन में मदद करते हैं। पेड़ों की पत्तियों, जड़ों और छाल का उपयोग दवाओं को तैयार करने के लिए किया जाता है। जंगली पादप जातियों में छिपे औषधीय गुणों की सहायता न मिली होती तो संसार के अनेक क्षेत्रों में प्रलय की जैसी स्थिति होती। सर्पगंधा, नयनतारा, गिलोय एवं रतालू वंश के जैसे अनगिनत पौधों ने मनुष्य के रोग निवारण में जो योगदान दिया वह किसी से छिपा नहीं है। पेड़ जानवरों और मनुष्यों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। विशाल, घने वृक्षों से भरे जंगल जंगली जानवरों के आवास के रूप में काम करते हैं और समृद्ध जैव विविधता के लिए योगदान करते हैं। पेड़ों से निकाली गई लकड़ी और अन्य सामग्री का उपयोग कई चीजों को शिल्प करने के लिए किया जाता है जो एक आरामदायक जीवन के लिए आवश्यक हैं। पेड़ पर्यावरण को शांत और खुशनुमा भी बनाते हैं। पादप और जीवधारी भले ही एक दूसरे के पूरक हों मगर जीवधारियों से अधिक संवेदनशील पादपों का जीवन है, इसीलिए आज बड़ी संख्या में कुछ पादप प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं।

यूरोप में जलवायु ने खड़ा किया राष्ट्रीय संकट

दुनियाभर से पर्यटक यूरोप में गर्मी की छुट्टियां मनाने आते हैं लेकिन इस बार कई यूरोपीय देशों का हाल गर्मी से बेहाल हो चुका है। खासतौर पर पश्चिम यूरोप में गर्मी की वजह से कई देशों ने इसे राष्ट्रीय संकट घोषित कर दिया है। अगले कुछ हफ्तों तक इससे बचने के लिए अपने नागरिकों और पर्यटकों को चेतावनी दे रहे हैं। यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी की वजह से कहीं सूखा तो कहीं जंगलों में आग लगने की खबरें सुर्खियों में है। वहीं प्रचंड गर्मी से यूरोपीय देशों के पर्यटन को धक्का भी पहुंच रहा है।

स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, यूके में गर्मी का पारा 37 डिग्री के पार जा चुका है। इन देशों के मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान क़रीब आठ से दस डिग्री तक और बढ़ सकता है। कम से कम अगले दो सप्ताह तक इस प्रचंड गर्मी से निजात मिलने की संभावना नहीं है। इधर, ठंडे प्रदेशों के लकड़ी के घरों में एसी और पंखे की व्यवस्था नहीं होती है। यहां घरों को भी इस तरह तैयार किया जाता है कि ठंड के मौसम में बाहरी तापमान का असर घर के अंदर नहीं हो। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तापमान बढ़ने से यहां लोगों किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। सूरज की तीखी धूप में बाहर निकलना चुनौती से कम नहीं। वहीं घरों का निर्माण ऐसे भीषण गर्मी को ध्यान में रखकर नहीं किया गया। जिससे घरों के अंदर भी लोग बेहाल हो रहे हैं। यह असंतुलित तापमान का असर ही है कि अब नॉर्वे और स्वीडन में भी एसी व पंखे बिकने लगे हैं। यहां इन चीजों का बाजार बन रहा है।

स्वीडिश जलवायु शोधार्थियों ने पहले ही इस बार देश में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी कर दी थी। जिससे यहां के बाजारों में पंखे और एसी उम्मीद से ज्यादा बिकने शुरू हो गये। स्पेन में हालात की गंभीरता को समझते हुए दिन में समुद्र तटों पर पर्यटकों के जाने की मनाही पहले ही हो चुकी है। हाल में ही स्पेन में पारा 40 डिग्री के पार जाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने तपती धूप में समुद्र बीच पर जाने, लेटने, बैठने या सीधे धूप के संपर्क में रहने पर रोक लगा दिया था। ताकि कम से कम लोग लू की चपेट में आए और वे गर्मी से बीमार नहीं हो। पारा औसत से अधिक होने पर दिन में सार्वजनिक कार्यक्रमों और खुले मैदान में बैठने पर भी मनाही कर दी गई। वहीं इटली पिछले 70 सालों के सबसे भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। जिससे वहां गर्मी से आपातकाल की घोषणा की गई। इस सूखे की सबसे ज्यादा मार चावल की खेती पर हुई है। लगातार गर्मी और कम बारिश की वजह से धान के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इटली में पिछले तीस वर्षों की औसत बारिश का आधा भी इस वर्ष नहीं हुआ है। सूखे के कारण देश का 30 प्रतिशत कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसमें धान की खेती यहां सबसे ज्यादा बर्बाद हुई है। इसका असर आने वाले दिनों में बाजार की महंगाई पर भी पड़ने वाला है। इंग्लैंड और वेल्स में मौसम विभाग ने अगले दो हफ्तों के लिए हीट अलर्ट जारी कर दिया है।

यहां आने वाले दिनों में तापमान औसत से ज्यादा रहेंगे। ऐसे में लोगों को दिन में कम से कम घर से बाहर निकले और शरीर में पानी की कमी नहीं हो इसकी भरपूर व्यवस्था रखने के सुझाव सार्वजनिक तौर पर दिये जा रहे हैं। वहीं सूखे व भयंकर गर्मी की वजह से रोम और पुर्तगाल के जंगलों में आग लग गई। इस वजह से आसपास के इलाकों का तापमान औसत से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि तापमान ऐसे ही प्रचंड रहा तो पुर्तगाल में भी गर्मी को राष्ट्रीय संकट घोषित किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक यूरोप में बिगड़े हालात को जलवायु संकट की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी अगर मौसम परिवर्तन को लेकर दुनिया सचेत नहीं हुई तो आने वाले दिन इससे कहीं ज्यादा घातक होने वाले हैं। यूरोप में असंतुलित तापमान का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी।

किसानों और खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं केंचुआ और उससे बनी खाद

प्रकृति ने केंचुओं को शायद किसानों की सेवा में हमेशा तैनात रहने और पर्यावरण संरक्षण में शानदार योगदान देने के लिए ही बनाया है। इसीलिए जगत में केंचुए को किसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा गया है। रेंगने वाले ये प्राणी खेतों में रहें या फिर किसानों के घर से निकलने वाले जैविक कूड़ा-कड़कट में, हर जगह ये किसानों की मुफ्त और लगातार सेवा करते रहते हैं। खेतों में रहने के दौरान मुफ्त श्रमदान करके केंचुए जहां मिट्टी को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पलटकर उसमें हवा और नमी के आवागमन का रास्ता तैयार करते हैं। वहीं किसानों के घर के इर्द-गिर्द रहने के दौरान केंचुए वहां के कूड़ा-कड़कट, अनाज की भूसी, राख, फसलों का अवशेष, पशुओं का गोबर और मूत्र बगैरह को सड़ाकर बेहतरीन जैविक खाद बनाते रहते हैं। केंचुआ खाद में 50-75 प्रतिशत प्रोटीन और 7-10प्रतिशत वसा के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

कीमत के लिहाज से भी केंचुआ खाद से मिलने वाले ये पोषक तत्व अन्य किसी भी स्रोत की तुलना में बेहद किफायती होते हैं। केंचुआ खाद के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी के भौतक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में भी सुधार होता है और उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं के अनुपात बेहतर बनता है। देशी कंपोस्ट और गोबर की खाद की तुलना में केंचुआ खाद के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। अपनी दानेदार प्रकृति की वजह से केंचुआ खाद, जमीन में हवा के आवागमन को और उसकी नमी सोखने की क्षमता को बढ़ाती है। केंचुए हरेक तरह का जैविक कूड़ा-कचरा खा सकते हैं और अपने मल तथा स्राव के रूप में शानदार जैविक खाद उत्सर्जित करते रहते हैं। केंचुओं के इन्हीं गुणों की वजह से इन्हें बाकायदा व्यावसायिक रूप से पाला जाता है और अतिरिक्त आमदनी के लिए भी अपनाया जाता है। केंचुओं के जरिये निर्मित जैविक खाद को केंचुआ खाद या वर्मीक पोस्ट कहते हैं। ये खाद, मिट्टी और फसल दोनों के लिए ही बेहद गुणकारी साबित होती है। इसीलिए केंचुआ पालन करके और इसकी खाद यानी वर्मीक पोस्ट का व्यावसायिक उत्पादन करके भी किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अच्छी प्रजाति वाले केंचुओं को यदि कूड़ा-कड़कट के साथ एक तिहाई गोबर और पशुओं में मल-मूत्र तथा बायो गैस के ठोस अवशेष (स्लरी) के साथ मिलाकर पाला जाए तो पोषक तत्वों से भरपूर क्वालिटी वाली केंचुआ खाद बनायी जा सकती है। इस खाद को फलों, सब्जियों, कन्द, अनाज, जड़ी-बूटी और फूलों की खेती के अलावा मुर्गी, मछली और पशु पालन में इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद साबित होता है। उत्तम किस्म की केंचुआ खाद, गंध रहित और पर्यावरण के अनुकूल होती है।

इसे 1, 2, 5, 10 और 50 किलो के थैलों में बेचा जाता है। केंचुआ खाद की क्वालिटी के हिसाब से बाजार में इसे 5 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक का भाव मिल जाता है। इतना ही नहीं, अन्य किसानों को 500 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से केंचुए बेचकर भी कमाई की जा सकती है। इसीलिए केंचुआ पालन अब एक लाभदायक व्यवसाय का रूप ले चुका है। केंचुआ खाद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए दो तरीके प्रचलित हैं- भीतरी और बाहरी। छोटे पैमाने पर केंचुआ खाद के उत्पादन के लिए भीतरी तरीका उपयुक्त है तो बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए बाहरी तरीका ही सही है। भीतरी विधि में फल-सब्जी के अवशेष, भूसा, दाने तथा फलियों के छिलके, पशुओं के मलमूत्र एवं खरपतवार जैसे कार्बनिक पदार्थों को छायादार क्षेत्र में रखा जाता है। तेजी से केंचुआ खाद बनाने के लिए इस कूड़ा-कड़कट पर पानी का पर्याप्त छिड़काव करके उसमें कुछ केंचुओं को छोड़ दिया जाता है। केंचुओं की संख्या कूड़े की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। कम कुड़े में ज्यादा केंचुए होंगे तो खाद अपेक्षाकृत जल्दी बनेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में कूड़े का नया ढेर भी जरा जल्दी यानी 3-4 महीने के भीतर बनाया जाना चाहिए, वर्ना केंचुओं का पोषण और उनकी वंशवृद्धि की रफ्तार घट जाएगी।

खरपतवारों से कैसे बचाएं सोयाबीन की फसल

खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक

सोयाबीन की चारामार के बारे में जाने किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। देश के सोयाबीन उत्पादन में 80 फीसदी हिस्सेदारी इसी राज्य की है। सोयाबीन की उपज क्षमता अन्य दलहन फसलों से अधिक है और यह मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है, लेकिन खरपतवारों के कारण इसकी फसल को 30-70 फीसदी तक हानी होती है। इसलिए सोयाबीन की फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए समय रहते खरपतवारों को नियंत्रित करना आवश्यक है। सोयाबीन की बोवनी का सर्वोतम समय जून से जुलाई मध्य तक माना जाता है। बोवनी के 20-45 दिनों के अंदर निराई-गुड़ाई करके खरपतवारों को नियंत्रित करना जरूरी है। खरपतवार खत्म करने के लिए कई तरह के केमिकल भी आते हैं, जिनका उपयोग किसान कर सकते हैं।

चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार

इन खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। यह मुख्य दो बीजपत्रीय पौधे होते हैं जैसे महकुंआ (अजेरेटम कोनीजाइडस), जंगली चौलाई (अमरेन्थस बिरिडिस), सफेद मुर्ग (सिलोसिया अजरेन्सिया), जंगली जूट (कोरकोरस एकुटैंन्गुलस), बन मकोय (फाइजेलिस मिनिगा), हजारदाना (फाइलेन्थस निरुरी) तथा कालादाना (आइपोमिया स्पीसीज) आदि।

सकरी पत्ती वाले खरपतवार

इस घास की प्रजाति के खरपतवारों की पत्तियां पतली व लंबी होती हैं। इन पत्तियों के अंदर समांतर धारियां पाई जाती हैं। ये एक बीज पत्री पौधे होते हैं जैसे सांवक (इकाईनोक्लोआ कोलोना), कोदों (इल्यूसिन इंडिका) आदि। मोथा परिवार के खरपतवार- इस प्रकार के खरपतवारों की पत्तियां लंबी और तना तीन किनारों वाला व सख्त होता है। जड़ों में गांठे होती हैं, जो भोजन एकत्र करके नए पौधों को जन्म देने में मदद करता है- जैसे मोथा (साइपेरस रोटन्ड्स, साइपेरस) आदि।

खरपतवारों से नुकसान

खरपतवार अधिक होने पर पौधों को पर्याप्त मात्रा में नमी, प्रकाश व पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते। इससे उनका विकास प्रभावित होता है। साथ ही इससे कई प्रकार के कीड़े, रोगाणु व बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए जल्दी इसे नियंत्रित करना जरूरी है।

साफ-सफाई और अच्छे बीज

खरपतवारों को रोकने के लिए बोवनी से पहले खेत को अच्छी तरह से साफ करें और सड़ी कंपोस्ट गोबर की खाद डालें। साथ ही प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें। सोयाबीन की फसल की बोवनी के 20-45 दिन के भीतर खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए पहली निराई-गुड़ाई 20-25 दिन बाद और दूसरी 40-45 दिन बाद करनी चाहिए। निराई-गुराई के लिए व्हील हो या ट्विन व्हील हो जैसे प्रयोग किया जा सकता है।

खरपतवारनाशी केमिकल

खरपतवारों को रोकने के लिए जिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसे खरपतवारनाशी कहते हैं। साथ ही सोयाबीन की चारामार दवा भी कहा जाता है। इन केमिकल के इस्तेमाल से प्रति हेक्टेयर लागत कम आती है। समय की भी बचत होती है, लेकिन इनका इस्तेमाल करते समय मात्रा को लेकर सावधानी बरतें, वरना नुकसान भी हो सकता है। सोयाबीन की चारामार दवा यानी कि खरपतवारनाशी कई प्रकार के होते हैं। इसकी मात्रा और किसी तरह से इस्तेमाल करना है, इसके संबंध में आप किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं।

बरतें ये सावधानियां

- सभी खरपतवारनाशी केमकिल के डिब्बों पर दिशा-निर्देश लिखे होते हैं। उन्हें ध्यान से पढ़ने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें।
- समय पर छिड़काव करना जरूरी है। समय से पहले या बाद में छिड़काव करने पर फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है।
- इनका पूरे खेत में एक समान छिड़काव करना चाहिए। इनका छिड़काव तेज हवा के बीच नहीं करना चाहिए।
- सोयाबीन में खरपतवारनाशी रसायनों की आवश्यक मात्रा को 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव करें।

400 बसों को सीएनजी देने का था दावा

इंदौर में गीले कचरे से बनी 1500 टन जैविक खाद

इंदौर। जागत गांव हमार

शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर 500 टन गीले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाए जाने वाले एशिया के सबसे बड़े संयत्र से 400 बसों को ईंधन देने की योजना थी, लेकिन सिर्फ 71 बसों को ईंधन के रुप में गैस दी जा रही है। इसमें 26 आई बसें है और 45 सिटी बसों को ईंधन दिया जा रहा है। सिटी बस प्रबंधन के पास फिलहाल सीएनजी वाली 100 सिटी बसें उपलब्ध हैं, लेकिन एआईसीटीएसएल अभी सभी बसों को गैस रीफिलिंग के लिए नहीं भेज रहा है। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बने बायो सीएनजी पंप की दूरी ज्यादा होने के कारण अभी कई बस आपरेटर वहां गैस रीफिलिंग के लिए बसें लाने-ले जाने को खर्चीला मान रहे हैं। यही वजह है कि अभी 50 फीसद सिटी बसें ही ईंधन के लिए वहां पर जा रही है। सिटी बसों को गैस रीफिलिंग के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड न जाना पड़े। इस वजह से शहर में राजीव गांधी चौराहा और रसोमा चौराहे पर गैस रीफिलिंग सेंटर बनाया जाना है। सिटी बस प्रबंधन ने अवंतिका गैस एजेंसी को इसका जिम्मा दिया गया है। यह प्लांट अभी तक तैयार हो जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई। इस प्लांट में गीले कचरे से करीब 1500 टन जैविक खाद अभी बनकर तैयार है। प्लांट तैयार करने वाली कंपनी ने खाद बिक्री करने वाली एजेंसी कृभको, राष्ट्रीय केमिकल व नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से 10 हजार टन खाद देने का अनुबंध किया है। जैविक खाद के पैकेट तैयार कर इन एजेंसियों को देने की तैयारी है।

पांच रुपए सस्ती मिलेगी गैस

सिटी बस प्रबंधन के अधिकारियों के मुताबिक अगले एक माह में यह रीफिलिंग सेंटर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बसों को शहर में गैस रीफिलिंग की सुविधा मिल सकेगी। इस प्लांट में तैयार हो रही बायो सीएनजी गैस सिटी व आई बस के संचालन के लिए बाजार मूल्य से 5 रुपए कम कीमत में एआईसीटीएस द्वारा अनुबंधित बस आपरेटर को उपलब्ध करवाई जा रही है।

16 टन गैस हो रही तैयार, निजी कंपनियों को दे रहे

इंदौर क्लीन एनर्जी एजेंसी द्वारा 150 करोड़ रुपए खर्च कर इस प्लांट को तैयार किया गया है। निगम कंपनी को गीला कचरा उपलब्ध करवा रहा है। इसके बदले में कंपनी द्वारा नगर निगम को प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रुपए दे रही है। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बायो सीएनजी गैस का प्लांट के पूरी क्षमता चालू होने के बाद अब यहां पर प्रतिदिन 16 टन बायो सीएनजी गैस तैयार हो रही है। इसमें से सिर्फ 3.5 टन गैस ही सिटी बसों को मिल पा रही है। शेष गैस कंपनी अभी निजी कंपनियों को बेच रही है। कंपनी अभी एचडी वायर कंपनी को 1.5 टन, अवंतिका गैस को 8.5 टन, एल एंड टी कंपनी को 2.5 टन प्रतिदिन गैस दी जा रही है।

हमारे प्लांट में 16 टन बायो सीएनजी गैस तैयार हो रही है। प्लांट से 26 आइबस व 45 सिटी बसों को गैस दे रहे है। इसके अलावा हम निजी कंपनियों को भी गैस उपलब्ध करवा रहे है। शहर में गैस रीफिलिंग सेंटर जैसे ही तैयार होंगे, हम निजी कंपनियों की गैस की मात्रा को कम कर बसों को देंगे।

- नितेश त्रिपाठी, प्रोजेक्ट हेड, इंदौर क्लीन एनर्जी

अवंतिका गैस एजेंसी को गैस रीफिलिंग सेंटर बनाने का जिम्मा दिया गया है। कंपनी अगले माह तक इसे तैयार कर देगी। अभी बसों को रात में गैस रीफिलिंग के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड पर भेजना पड़ता है। एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में बसों को वहां से गैस देना संभव नहीं है।

- संदीप सोनी, सीईओ एआईसीटीएसएल

-देश के कृषि विशेषज्ञों ने दी सलाह, कहा

मौसम को देख किसान करें खरीफ फसलों की बोवनी

भोपाल। जागत गांव हमार

इस समय ज्यादातर प्रदेशों में मानसून आ गया है, मानसून आने के साथ ही किसान खरीफ की फसलों की बुवाई शुरू कर देते हैं। ऐसे में किसानों के लिए जानना सबसे जरूरी है कि वो इस हफ्ते खेती-किसानी में क्या करें। आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हर हफ्ते किसानों के लिए मौसम आधारित संबंधित कृषि सलाह जारी करता है। वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है की किसी प्रकार का छिड़काव न करें और खड़ी फसलों व सब्जी नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें। धान की नर्सरी अगर 20-25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेमी और पौध से पौध की दूरी 10 सेमी रखें। उर्वरकों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट/हेक्टेयर की दर से डाले, और नील हरित शैवाल एक पैकेट/एकड़ का प्रयोग उन्ही खेतों में करें जहां पानी खड़ा रहता हो, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सकें। धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं। जिससे आने वाले दिनों में वर्षा का ज्यादा से ज्यादा पानी खेतों में संचित हो सके। धान की पौधशाला मे यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है, तो इसमे लौह तत्व की कमी हो सकती हैं। पौधों की यदि ऊपरी पत्तियां पीली और नीचे की हरी हो तो यह लौह तत्व की कमी को दर्शाता है। इसके लिए 0.5 प्रतिशत फेरस सल्फेट +0.25 प्रतिशत चूने के घोल का छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।

मक्का की भी करें बोवनी| मृदा में पर्याप्त नमी को ध्यान में रखते हुए किसान इस सप्ताह मक्का की बोवनी शुरू कर सकते हैं। संकर किस्में ए एच-421 व ए एच-58 और उन्नत किस्में पूसा कम्पोजिट-3, पूसा कम्पोजिट-4 की बोवनी शुरू कर सकते हैं। बीज की मात्रा 20 किलोग्राम/हेक्टयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60-75 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 18-25 सेमी रखें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 1 से 1.5 किलोग्राम/ हैक्टर 800 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।

प्रमाणित बीज ही खरीदें| कम समय में पकने वाली अरहर की किस्मों (पूसा 991, पूसा 992, पूसा 2001, पूसा 2002) की बोवनी जुलाई में मृदा में पर्याप्त नमी को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। किसानों से यह सलाह है कि वे बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राईजोबियम और फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणुओं फंफूद के टीकों से अवश्य उपचार कर लें।

वर्षाकालीन फसल की बोवनी करें

कद्दूवर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसल की बोवनी करें। लौकी की उन्नत किस्में पूसा नवीन, पूसा समृद्धि करेला की पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी, सीताफल की पूसा विश्वास, पूसा विकास तुरई की पूसा चिकनी धारीदार, तुरई की पूसा नसदार और खीरा की पूसा उदय, पूसा बरखा आदि किस्मों की बुवाई मृदा में पर्याप्त नमी को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढ़ों में गोबर की खाद मिलाकर 5.0 मिली क्लोरपाईरिफॉस एक लीटर पानी में मिलाकर गड्ढ़ों में डालकर गड्ढ़ों को पानी से भर दें ताकि दीमक और सफेद लट से बचाव हो सके।

देशी का करें प्रयोग

किसान देशी खाद का ज्यादा प्रयोग करें, ताकि भूमि की जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। मृदा जांच के बाद उर्वरको की संतुलित मात्रा का उपयोग करें खासतौर पर पोटाश की मात्रा बढ़ाएं ताकि पानी की कमी के दौरान फसल की सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ सके। वर्षा आधारित और बारानी क्षेत्रों में भूमि मे नमी संचयन के लिए पलवार (मल्चिंग) का प्रयोग करना लाभदायक होगा।

खरीफ एवं रबी के लिए कलस्टरवार निर्धारित

31 जुलाई तक किसान करा सकेंगे फसल बीमा

भोपाल।

किसान 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करा सकेंगे। दरअसल यह बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022- 23 मौसम खरीफ एवं रबी के लिए कलस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। किसानों को फसल बीमा कराने के बाद ही उनकी मौसम या अन्य प्राकृतिक घटना की वजह से खराब होने वाली फसल की बीमा राशि मिल सकेगी। योजना के तहत खरीफ 2022 के लिए अधिसूचित पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे 31 जुलाई तक निर्धारित किए जाएंगे। बैंकों द्वारा बीमित किसानों की

प्रविष्टि के लिए भारत सरकार का फसल बीमा पोर्टल पर बैंकों द्वारा समय-सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। बोई गई फसल की क्षति के समय कृषकों को हानि से बचने के लिए तथा बोई जाने वाली फसल में किसान द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमांकन की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व यानि 29 जुलाई तक बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी बैंकों उपलब्ध कराया जाना है। किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2022 अन्तर्गत प्रदेश में नेशनल काप इन्श्योरेन्स पोर्टल पर भू - अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी।

दर्ज करनी होगी सही जानकारी

बीमाकर्ता बैंकर्स, कामन सर्विस सेन्टर, स्वंय कृषक द्वारा संगत खसरा नंबर का चयन कर धारित भूमि का बीमा किया जा सकेगा। किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी बैंक द्वारा एनसीआइपी पोर्टल पर दर्ज की जाना है जिससे किसानों को समय पर सही बीमा पालिसी जारी हो सकेगी।

-फसल बीमा के लिए बैंकों को निर्देश जारी

बैंकों को फसल में परिवर्तन की सूचना 29 जुलाई तक दें

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिए किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कम्पनियों को कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिये बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अपर संचालक फसल बीमा ने बताया कि किसानों को बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से दो दिन पहले 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगी।

जानकारी दर्ज होना जरूरी

किसानों को समय पर सही पॉलिसी जारी करने के लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेस पोर्टल (एनसीआई) पर जानकारी दर्ज होना जरूरी है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के बीमा पंजीयन के दौरान खसरा नम्बर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें।

भू-अभिलेख एकीकरण का कार्य जारी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2022 के लिए प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (एनसीआईपी) पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमिधारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप-डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। बीमाकर्ता (बैंकर्स, कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं कृषक) संगत खसरा नम्बर का चयन कर धारित भूमि का बीमा कर सकेगा।

किसानों को मिले सही दाम, उपज की तौल त्वरित और सही हो

-मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक भोपाल मंडी का किया दौरा, कहा

भोपाल। मप्र राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक जीव्ही रश्मि द्वारा भोपाल मंडी का दौरा किया गया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय कृषि बाजार, एमपी फार्मगेट एप, सौदा पत्रक मोबाइल एप, रूट्स एंड वेजीटेबल एप, ई-मंडी एप्लीकेशन का अवलोकन किया गया। भ्रमण के दौरान प्रबंध संचालक द्वारा व्यापारियों से चर्चा की गई। फल सब्जी मंडी यार्ड का भी भ्रमण प्रबंध संचालक द्वारा किया गया। मंडी में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। प्रबंध संचालक द्वारा मंडी प्रशासन को निर्देश दिए गए कि कृषकों की सुविधा के संबंध में हर संभव कार्रवाई करें। हम्माल एवं तुलावाटों के प्रकरणों में भी त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मंडी में व्यापार कर रहे व्यापारियों को भी व्यापारिक रूप से फैसिलिटेट करने के निर्देश दिए गए।

मंडी में ही हो भुगतान

विपणन व्यवस्था को देखने के लिए प्रबंध संचालक द्वारा अन्य आगामी दिनों में पुनः भोपाल मंडी के दौरे की बात कही गई। प्रबंध संचालक द्वारा मंडी प्रशासन को अपने दौरे के अंत में निर्देश दिए गए कि कृषकों को मंडी प्रांगण में अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था मंडी प्रशासन करे। किसानों को सही दाम मिले, उनकी उपज की तौल त्वरित एवं सही हो। साथ ही भुगतान मंडी प्रांगण में उसी दिन कृषकों को प्राप्त हो ऐसे निर्देश दिए गए।

-प्रशासन की नाक के नीचे चल रही कालाबाजारी

मुरैना में 270 का यूरिया 320 रुपए का बेच रहे व्यापारी

मुरैना। जागत गांव हमार

फसलों के लिए यूरिया खाद की मांग बढ़ते ही बाजार में खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई है। सरकारी गोदाम व दुकानों की तुलना में बाजार में यूरिया का एक बोरा 50 रुपए महंगा बिक रहा है। अभी तो गिनती के ही किसानों ने ही यूरिया की मांग की है और अभी से खाद के लिए लाइन लगने से किसान परेशान और आगे आने वाले खाद के संकट को लेकर चिंतित भी हैं। खाद लेने वाले किसानों ने बताया, कि सरकारी गोदाम पर 270 रुपए में 50 किलो यूरिया का बोरा मिल रहा है, वही बाजार में 320 रुपए का मिल रहा है। सोसायटियों पर अब तक खाद पहुंचा नहीं है, इसलिए खाद के लिए गोदामों पर कतारें लगने लगी हैं। ऐसे समय में भी यूरिया का संकट दिखने लगा है।

डीएपी 150 रुपए महंगा

यूरिया खाद की बढ़ती मांग और कमी के बाद किसानों को डीएपी खाद के दामों ने भी जोर का झटका दिया है। सरकार ने डीएपी खाद के दाम अचानक से बढ़ा दिए हैं। सर्दी के सीजन में जब गेहूं की फसल के लिए डीएपी की सबसे ज्यादा मांग दी थी डीएपी का एक बोरा 1200 रुपए का था, जिसके अब 1350 रुपए कर दिए गए हैं। एमपी एग्रो व इफको गोदामों के प्रबंधकों के अनुसार दाम अप्रैल महीने में ही बढ़ गए थे, लेकिन बढ़े हुए दाम इस बार आए लाट में आए हैं।

रास नहीं आ रहा नैनो यूरिया

इफको ने यूरिया खाद से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली नैनो यूरिया बनाया है। यह आधा लीटर की बोतल में आने वाला लिक्विड खाद है, जिसे पानी में मिलाकर फसल पर छिड़का जाता है। कृषि वैज्ञानिक संदीप सिंह तोमर के अनुसार 500 एमएल नैनो यूरिया 50 किलो के यूरिया के बोरे से भी ज्यादा असरदार है, यह जमीन व फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। कृषि वैज्ञानिकों के इन दावों के बाद भी किसानों को नैनो यूरिया रास नहीं आ रहा। एमपी एग्रो के गोदामों से उन सभी किसानों को नैनो यूरिया की बोतल सशर्त दी जा रही है। पांच बोरे यूरिया पर एक नैनो यूरिया की बोतल दी जा रही है, जिसे किसान सिर दर्द मान रहे हैं।

– बारिश के कारण प्रभावित हुई कूनों में अफ्रीकी चीतों की तैयारियां

बारिश से रुके कूनो में अफ्रीकी चीतों के कदम 15 अगस्त को आने की संभावना भी हुई धूमिल

भोपाल। विशेष संवाददाता

कूनो नेशनल पार्क में 15 अगस्त को अफ्रीकी चीतों के आने की संभावना बारिश के कारण धूमिल होती दिख रही है। क्योंकि बारिश के कारण कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बसावट को लेकर चल रही तैयारियां रूक गई है, जो 15 अगस्त तक मुश्किल ही पूरी होगी, इसलिए अब अफ्रीकी चीतों का कूनो में आगमन बारिश के बाद ही संभव हो सकेगा।

यहां बता दें कि, कूनो पार्क में अफ्रीकी चीतों को बसाने के लिए व्यवस्थाएं देखने के लिए नामीबिया से विशेषज्ञ डॉ. जारी मार्कर, दक्षिण अफ्रीका से विंसेंट, डॉ. एड्रिन देहरादून भारतीय वन्य प्राणी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वायवी झाला और विपिन के साथ कूनो पार्क आए थे। उन्होंने कूनो में चीतों के बसाए जाने की तैयारियों का अवलोकन करते हुए उस विशेष बाडे का भी जायजा लिया, जिसे चीतों को रखने के लिए विकसित किया गया है। इस दौरान अफ्रीकी टीम को कूनो में चार-पांच जगह छोटी-छोटी कमियां मिली थी, जिन्हें दूर करने के लिए कूनो के अफसरों से कहा गया था। बताते है कि कूनो पार्क प्रबंधन ने दल के लौटने के बाद उन कमियों को दूर करवाने का काम शुरू करवाया, जिसे अफ्रीकी दल के द्वारा बताया गया, लेकिन 21 जून से बारिश शुरू हो गई, इसलिए पार्क प्रबंधन को ये काम बीच में रोकना पड़ा। अब ये कमियां बारिश के बाद ही दूर हो पाएगी और तभी अफ्रीकी चीतों का कूनो में आगमन हो सकेगा।

पांचों सेक्टर में बनने हैं जलस्त्रोत

दल को दिखाने के लिए प्रबंधन ने सैंपल के तौर पर एक-दो जगह ही चीतों के पानी पीने के लिए जल स्त्रोत बनाए थे, यह जलस्त्रोत निरीक्षण करने आए दल को पसंद आ गए, इसलिए अब उसी डिजायन के अनुसार बाड़े के पांचों सेक्टर में जलस्त्रोत तैयार किए जाने के लिए दल के द्वारा कहा गया था। जिनका काम होना बाकी है। इसके अलावा दल को बाड़े में कुछ छोटी-मोटी कमियां मिलीं थी जिन्हें कूनो प्रबंधन द्वारा दूर करने का काम किया जा रहा है।

बाड़े से बाहर नहीं निकाले जा सके 3 तेंदूए

कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों को रखने के लिए एक विशेष बाड़ा तैयार किया गया है। जिसमें 5 तेंदूए और 2 हायना मौजूद है, जो चीतों के लिए परेशानी का कारण बन सकते है। इसलिए कूनो पार्क प्रबंधन तेंदूए और हायना को बाडे से बाहर निकालेगा। कूनो के अधिकारियों की माने तो अफ्रीकी चीतों के बाडे से 2 तेंदूए तो बाहर निकाल दिए गए, लेकिन 3 तेंदूए और 2 हायना अभी बाहर नहीं निकाले जा सके है, बारिश के कारण इस काम में देरी हुई है। बारिश थमते ही तेंदूए और हायना को बाड़े से बाहर निकाल दिया जाएगा।

आएगी देहरादून की टीम

बारिश के कारण कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों की क्या-क्या तैयारियां रूक गई है, यह देखने के लिए देहरादून भारतीय वन्य प्राणी संस्थान की एक टीम अगले सप्ताह कूनो नेशनल पार्क का दौरा करने के लिए आएगी। इस टीम में देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वायवी झाला सहित अन्य विशेषज्ञ अधिकारी शामिल रहेंगे। यह टीम कूनों में बारिश के बीच अफ्रीकी चीतों की तैयारियां कैसे पूरी हो, इस संबंध में कूनो का दौरा करने के बाद कूनो के अफसरों को दिशा निर्देश देगी।

कूनो में अफ्रीकी चीतों को बसाने की तैयारियां चल रही है, लेकिन इसमें बारिश से थोड़ा अवरोध उत्पन्न हुआ है। देहरादून की एक टीम भी जल्द ही कूनो का दौरा करने के लिए आएगी। टीम के दौरा करने के बाद ही अफ्रीकी चीतों के आने की तिथि निश्चित होगी।

पीके वर्मा, डीएफओ, कूनो श्योपुर

धरना-प्रदर्शन भी किया, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

कॉलेज नहीं होने के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं कई छात्र

बड़ौदा में कॉलेज की दरकार, ध्यान दो सरकार

भोपाल। संवाददाता

भले ही बड़ौदा कस्बे को 32 गांवों की राजधानी कहा जाता है, इसके बाद भी बड़ौदा कस्बा शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। अकेले बडौदा कस्बे की आबादी 25 हजार के आसपास है, बाजवूद इसके यहां एक सरकारी कॉलेज तक नहीं है। जिसके कारण बडौदा कस्बे सहित बत्तीसा क्षेत्र के लगभग तीन सैंकड़ा छात्र-छात्राओं को कॉलेज की पढ़ाई के लिए या तो श्योपुर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है या फिर राजस्थान के बारां का रुख करते हैं। यही नहीं कॉलेज नहीं होने से कई छात्र-छात्राएं तो 12वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ देते हैं।

बड़ौदा में एक अदद सरकारी कॉलेज की मांग बरसों पुरानी है, इस मांग को लेकर क्षेत्र के युवा धरना प्रदर्शन करने के साथ-साथ केन्द्रीय मंत्री तक को ज्ञापन सौप चुके है। इसके बाद भी शासन-प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़ौदा सहित बत्तीसा क्षेत्र के आधा सैकड़ा गांवों

के अभिभावकों और छात्र-छात्राओं का कहना है कि बड़ौदा में कॉलेज खोलने की मांग काफी पुरानी है, लेकिन सरकार इस मांग को दरकिनार कर रही है। जबकि सरकार ने चार साल पहले कराहल और ढोढर में कॉलेज खोल दिए, जबकि वहां छात्रों की संख्या में भी पर्याप्त नहीं है। इधर बड़ौदा के छात्र-छात्राएं आज भी 25 किलोमीटर दूर श्योपुर जिला मुख्यालय के कॉलेज की ओर देखना पड़ता है। हालांकि इस मांग को लेकर छात्र संगठनों द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन नतीजा आज भी ढाक के तीन पात ही है।

छात्राओं की छूट जाती है पढ़ाई

बड़ौदा में सरकारी कॉलेज नहीं होने के कारण कई छात्राएं 12वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके अभिभावक उन्हें बाहर पढ़ने नहीं जाने देते तथा कई परिवार निजी कॉलेज में पढ़ाई की फीस का बोझ नहीं उठा पाते है। यहीं वजह है कि बड़ौदा में कॉलेज खोलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके बाद भी बड़ौदा में सरकारी कॉलेज नहीं खोला जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री को दे चुके हैं ज्ञापन

बड़ौदा में कॉलेज की मांग को लेकर मुरैना-श्योपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी छात्र संगठनों द्वारा कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। पिछले दिनों चुनावी कैंपेन में आए तोमर के समक्ष एक बार फिर स्थानीय नागरिकों ने कॉलेज की मांग उठाई है। जबकि इसके पहले कई छात्र धरना भी चुके है।

बड़ौदा में कॉलेज के संबंध में हमसे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जो जानकारियां मांगी गई थी, वो हमारे द्वारा भेजी जा चुकी हैं।

डॉ. एसडी राठौर, प्राचार्य, पीजी कॉलेज श्योपुर

लगाए गए पौधों में बरगद, पीपल, आम, जामुन, आंवला, शीशम, तींसा जैसी छायादार व फलदार प्रजाति के पौध

हरियाली कायम रखने लगाएंगे 40 हजार पौधे

-20 हजार लोग 75 फीसदी पौधों का कर चुके रोपण

भोपाल। जागत गांव हमार

भोपाल शहर को हरा-भरा रखने के लिए 20 हजार लोग सामने आ चुके हैं। ये 40 हजार पौधे खरीद चुके हैं। इनमें से 75 प्रतिशत पौधे लगा भी चुके हैं। लगाए गए पौधों में बरगद, पीपल, आम, जामुन, आंवला, शीशम, तींसा जैसी छायादार व फलदार प्रजाति के पौधे हैं। वर्षा का यह शुरुआती समय है। आगे इनकी संख्या और बढ़ेगी। दरअसल, बीती गर्मी ने लोगों को खूब सताया है। जिसके बाद भोपाल को हरा-भरा बनाने की चिंता दिखाई दे रही है। इसके लिए आम नागरिक स्वेच्छा से सामने आ रहे हैं। भोपाल वन वृत्त के जिलों की 18 नर्सरियों से अब तक 85 लाख पौधों की बिक्री हुई है। इनमें से 48 हजार 880 पौधे आम लोगों ने खरीदे हैं। जिनमें भोपाल के 20 लोग हैं, बाकी के विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर जिले के लोग हैं। बाकी के पौधे वन विभाग, नगर निगम, पंचायतें समेत अन्य योजनाओं में खरीदे गए हैं। इन पौधों के पेड़ बनने के बाद भोपाल समेत आसपास के जिलों में हरित आवरण बढ़ेगा। पौधे जामुन, आम, बरगद, पीपल, जामुन, बीजा, तींसा, आचार, ईमली, हर्रा, बेहड़ा, शीशम, तेंदू प्रजाति के हैं।

हरित आवरण घट रहा

गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में निर्माण कार्यों के चलते पेड़ों की कटाई हुई है। कुछ पौधे उम्रदराज होने के कारण वर्षा में गिर रहे हैं। सड़कों के किनारे खड़े हजारों पौधों के तने तक सीमेंट कांक्रीट व डामर कर दिया है, जिसके कारण ये कमजोर हो रहे हैं। नतीजा यह है कि हरित आवरण घट रहा है। यह बात समय-समय पर सामने आ चुकी है। विभिन्न रिपोर्ट में सामने आ चुकी है।

पांच जिलों में हुई पौधों की खरीदी

खरीदार	खरीदे पौधे
आम लोग	48,880
वन विभाग	40,63,487
पंचायतें	6,900
मनरेगा योजना	16,500
स्कूल शिक्षा विभाग	1,556
अन्य शासकीय विभाग	52,074
अशासकीय संस्था, संगठन	35,414
विस्तार वानिकी	78,206
कार्य आयोजना क्रियान्वयन	5,23,451
कैम्पा योजना	32,00,280
ग्रीन इंडिया मिशन	1,52,535
राज्य लघु वनोपज संघ	92,015
अन्य	2,04,304
किसान	25,861
कुल	85,01,463

जिलेवार पौधे लगाने का लक्ष्य

- 16 लाख भोपाल शहर व आसपास
- 10 लाख रायसेन जिले में
- 07 लाख विदिशा में
- 08 लाख सीहोर में
- 02 लाख राजगढ़ में

इन प्रजाति के पौधे की ज्यादा बिक्री

- 19 लाख सागौन के
- 06 लाख आंवला के
- 01 लाख महुआ
- 07 लाख बांस

अब तक 85 लाख पौधों का नर्सरियों से उठाव हो चुका है। अभी भी मांग के अनुरूप पौधे उपलब्ध हैं। इच्छुक ले सकते हैं। जब ये पौधे पेड़ बनेंगे तो निश्चित ही हरित आवरण बढ़ेगा।
- एचसी गुप्ता, सीसीएफ, सामाजिक वानिकी भोपाल वन वृत्त

गौ-शालाओं में 21 हजार पौधे रोपेगा मप्र गौ-संवर्धन बोर्ड

अध्यक्ष मप्र गौ-संवर्धन बोर्ड स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने बताया कि हरियाली अमावस्या 28 जुलाई को गौ-संवर्धन बोर्ड द्वारा प्रदेश की गौ-शालाओं में 21 हजार पौध-रोपण का लक्ष्य तय किया गया है। सभी पंजीकृत गौ-शालाओं में 5-5 पौधे और आगर-मालवा के सालरिया में स्थित कामधेनु गौ-अभयारण्य परिसर में बड़ी संख्या में पौध-रोपण होगा। उन्होंने बताया कि हरियाली अमावस्या के दिन ही रीवा जिले के 'बसावन मामा' और 'गौ-वंश वन्य विहार', ग्वालियर जिले के रानीघाटी परिक्षेत्र और लालटिपारा गौ-शाला में संतों की उपस्थिति में पौध-रोपण किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा भी प्रदेश के कार्यालय परिसरों में पौध-रोपण किया जाएगा। उन्होंने लोगों से पौध-रोपण में भाग लेने की अपील की है।

शिवपुरी में भी वृहद पौधरोपण को सफल बनाने कसी कमर

इधर, शिवपुरी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह की अध्यक्षता में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन संपूर्ण जिले में किया जाना है। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एडीआर भवन के सभाकक्ष में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी शैलेश अवस्थी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग शिवपुरी देवेन्द्र सुंदरयाल, जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र कुमार चढार, अपना घर आश्रम शिवपुरी के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल उपस्थित रहे। बैठक में तय किया गया कि 15 अगस्त तक जिला मुख्यालय सहित संपूर्ण विकासखंड पर व तहसील विधिक सेवा समिति अन्य समस्त शासकीय विभागों को समन्वय से हजारों पौधों का रोपण कराकर उनकी संवर्धन व संरक्षण की जिम्मेदारी आम लोगों को दिलाना है।

-मध्य प्रदेश की फसलों से आय दोगुना करने में अहम भूमिका

बढ़ता किसान, भारत की शान

भोपाल। जागत गांव हमार

खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल, खाद, उर्वरक और कीटनाशकों के रेट में पिछले एक साल में 10-20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2021 से जनवरी 2022 के बीच डीजल औसत 15-20 रुपए लीटर महंगा हुआ है। जबकि एनपीके उर्वरक की 50 किलो की बोरी 265 से 275 रुपए महंगी हुई है। जबकि साल 2022-23 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40 रुपए प्रति क्विंटल और पिछले साल (खरीद विपणन सीजन 2021-22) के लिए धान की एमएसपी में 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी। जबकि इस दौरान कीट, रोग और खरपतवार नाशक दवाओं में 10-20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। खेती की बढ़ती लागत के अलावा किसान एमएसपी से कम रेट पर बिकती फसलों से भी परेशान हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस और पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दावा किया है कि तटीय राज्य, ओडिशा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन किसानों के लिए आय सृजन का मुख्य स्रोत पाया गया है। यही

नहीं, 11 राज्यों- पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना में खेत फसलों का आय सृजन में मुख्य योगदान है। 14 राज्यों - जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, झारखंड, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पिछले चार/पांच वर्षों की कुल आय में बागवानी का प्रमुख हिस्सा रहा है। लद्दाख में किसानों की आय सृजन में कुल वृद्धि 125.44 फीसदी से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 271.69 प्रतिशत तक है। किसानों की आय में वृद्धि खेत फसलों, बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन और कृषि / गैर-कृषि उद्यमों सहित कृषि के सभी क्षेत्रों में स्पष्ट दिख रहा है। देश के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आईसीएआर ने देश भर के ऐसे असंख्य किसानों में से 75,000 सफल किसानों की सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण किया है। आईसीएआर-केवीके ने गांवों को गोद लेकर, नवीन तकनीकी विकल्पों और अच्छी कृषि पद्धतियों के द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्रित दृष्टिकोण के साथ किसानों का मार्गदर्शन किया है। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर केन्द्र सरकार और आईसीएआर के प्रयासों के कारण बड़ी संख्या में किसानों की आय दोगुनी से ज्यादा हो गई है। वहीं यह भी दावा किया गया है कि असम (27.17 फीसदी), उत्तराखंड (29.97 फीसदी), अरुणाचल प्रदेश (36.55 फीसदी), नागालैंड (42.37 फीसदी), त्रिपुरा (44.49 फीसदी) और मणिपुर (49.01 फीसदी) में अतिरिक्त आय का मुख्य स्रोत पशुधन हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
रहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)